



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

RECEIVED
11/8/02

सं. 694]

No. 694]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 1, 2002/श्रावण 10, 1924

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2002/SRAVANA 10, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2002

सं. 11/2002—2007

का.आ. 818(अ).— निर्यात और आयात नीति, 2002-2007 के पैरा 1.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या-22) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात और आयात नीति, 2002-2007 में निम्नलिखित संशोधन/शुद्धियाँ करती है:-

1. “निर्यात अनुबंधों को मूल्य वर्ग में डालना” से संबंधित पैरा 2.40 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

“सभी निर्यात अनुबंधों और बीजकों को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या भारतीय रूपयों के मूल्य वर्ग में डाला जाएगा लेकिन निर्यात आय को केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में ही प्राप्त किया जाएगा। वे अनुबंध जिनके लिए एशियल निकासी संघ (ए सी यू) के माध्यम से भुगतान प्राप्त किए जाते हैं उन्हें ए सी यू डालर के मूल्य वर्ग में डाला जाएगा। उपयुक्त मामलों में केन्द्र सरकार उस पैरा के प्रावधान में छूट दे सकती है। एग्जिम बैंक/भारत सरकार की ऋण प्रक्रिया में निर्यात अनुबंधों और बीजकों को भारतीय रूपयों के मूल्य वर्ग में डाला जाएगा”।

2. “निर्यात निष्पादन स्तर” से संबंधित पैरा 3.72 की टिप्पणी: 1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में स्थित यूनिटें “विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में 5 करोड़ रूपए का औसत पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य/रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्य प्राप्त कर लेने पर लघु

उद्योग/लघु क्षेत्र/कुटीर क्षेत्र की यूनिटें/के वी आई सी या के वी आई बी के पास पंजीकृत यूनिटें/उत्तर पूर्व राज्यों, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में स्थित यूनिटें/हथकरघा, हस्तशिल्प, हाथ के बुने कालीनों, रेशमी कालीनों का निर्यात करने वाली यूनिटें/स्वर्ण स्टेट्स धारक निर्यातक/लैटिन अमेरिका और सी आई एस/उस सहारा अफ्रीका के देशों को निर्यात करने वाले निर्यातक, आई एस ओ 9000 (सीरीज) या आई एस ओ 14000 (सीरीज) या एच ए सी सी पी प्रमाणन या डब्ल्यू एच ओ जी एम पी या एस ई आई सी एम एम स्तर 2 और उससे अधिक प्रमाणन स्टेट्स वाली यूनिटें निर्यात सदन स्तर हेतु हकदार होंगी। निर्यात सदन स्तर प्राप्त करने के लिए सेवा निर्यातकों और कृषि निर्यातकों (अनाजों के अलावा) पर भी यही न्यूनतम सीमा लागू होगी।”

3. पैराग्राफ 4.4.5 (ख) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

“आंशिक रूप से प्रोसेस्ड आभूषण, सिल्वर वायर, सिल्वर स्ट्रिप्स और अन्य वस्तुओं सहित मैङ्गालियन्स और सिक्के (लीगल टैन्डर किस्म के सिक्कों और किसी इन्जीनियरी वस्तुओं को छोड़कर) सहित चांदी के आभूषण जिनमें भार के रूप में 50 प्रतिशत से ज्यादा चांदी हो।”

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/26/ए एम 03/पी सी-4]

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं संचित

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2002

No. 11/2002—2007

S.O. 818(E).— In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.1 of the Export and Import Policy, 2002-07, the Central Government hereby amends/ corrects the Export and Import Policy, 2002-07 as under:

1) Para 2.40 pertaining to “Denomination of Export Contracts” is amended as under:

“All export contracts and invoices shall be denominated either in freely convertible currency or Indian Rupees but the export proceeds shall be realized in freely convertible currency only. Contracts for which payments are received through the Asian Clearing Union (ACU) shall be denominated in ACU Dollar. The Central Government may relax the provision of this paragraph in appropriate cases. Export contracts and invoices can be denominated in Indian rupees against EXIM Bank / Government of India line of credit.”

- 2) Note:1 of para 3.7.2 pertaining to "Export Performance Level" is amended as under:

"Units in Small Scale Industry/Tiny Sector/Cottage Sector/Units registered with KVICs or KVIBs/ Units located in North Eastern States, Sikkim and J&K/ Units exporting handloom, handicrafts, hand knotted carpets, silk carpets/exporters holding golden status/exporters exporting to countries in Latin America and CIS/sub Saharan Africa, units having ISO 9000 (series) or ISO 14000 (series) or HACCP Certification or WHO-GMP or SEI CMM level 2 and above certification status, shall be entitled for export house status on achieving average FOB/FOR value of Rs.5 crore during the preceding three licensing years. The same threshold limit shall be applicable to the service exporters and agri exporters (other than grains) for obtaining Export house status."

- 3) Paragraph 4.4.5 (b) is amended as under:

"Silver Jewellery including partly processed jewellery , silver wire, silver strips, and any article including medallions and coins (excluding the coins of the nature of legal tender and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight;"

This issues in public interest.

[F. No. 01/94/180/26/AM03/PC-IV]

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade & Secy.

